>

Title: Need to review export-import policy of cotton to save the cotton growers from incurring losses.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): सभापति महोदय, भारत के किसानों ने नई टेक्नोलोजी स्वीकार कर बी.टी. कपास का उत्पादन बढ़ा दिया है। पिछले पांच-सात वर्षों में 86 हेक्टर भूमि से 2010-11 में बढ़ाकर 1.11 करोड़ हेक्टर में उत्पादन किया है तथा कपास उत्पादन 244 बेल (गट्ठे) थे, उससे बढ़ाकर 334 बेल (गट्ठे) तक पहुंचा दिया है। सन् 2011-12 में 122 लाख हेक्टर से 365 बेल होने की संभावना है। किंतु वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कपास मिल मालिकों के इरादे पर कपास आयात निर्यात नीति में परिवर्तन कर किसानों को बेहाल कर दिया है। गिरे हुए दर (1000 रुपए की धट) से कपास उत्पादकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सीसीआई काटन कार्पोरेशन को भी कम दर से कपास बेचने पर 300 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदाज है। सरकार की गलत नीतियों के कारण लाखों किसानों का भविष्य धूल में मिला दिया। वे उत्पाद के लिए मारक साबित हुए गत वर्ष में कपास के विकास के साथ की खिलवाड़ से निकास कम रही। इस वर्ष 30 लाख बेल (गट्ठे) ज्यादा उत्पादन होने के बावजूद यह केरीओवर स्टोक 80 लाख बेल (गट्ठे) का बोझ उठाना पड़ रहा है।

समृद्ध देशों ने " दोहा राउंड " में कपास पर उनके देशों की भारी सब्सिडी कम करने की मांग की है। चीन के बाद भारत कपास उत्पादक में दूसरे नम्बर पर पहुंचा है। कम उत्पाद से परिचित भारत के कपास उत्पादक ने कपास उत्पादन 278 किलो से 521 किलो तक पहुंचाया है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि आज के तारंकित प्रश्न 264 बाजार हस्तक्षेप योजना हेतु आबंटन के जवाब के तहत कृषि मंत्री ने अपने उत्तर में लोकसभा को अवगत कराया कि गुजरात सहित आठ राज्यों में कपास उत्पादन का योग्य मूल्य नहीं मिल रहा है। उनकी कोई फरियाद की मांग आज तक नहीं आई है। मैं इससे सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे गुजरात के कृषि मंत्री जी ने पांच दिसम्बर तथा मैंने 12 दिसम्बर 2011 को इसके बारे में कृषि मंत्री माननीय शरद पवार जी को अवगत कराया है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि सरकार कपास आयात-निर्यात नीति का पुनः अवलोकन करे और कपास उत्पादन को होने वाली हानि से बचाए।